भारत सरकार
खान मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. †3946
दिनांक 12.08.2026 को उत्तर देने के लिए

खनन निगरानी प्रणाली

†3946. श्री जी. कुमार नायकः

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान खनन निगरानी प्रणाली (एमएसएस) और अन्य रिमोट सेंसिंग उपकरणों के माध्यम से वर्ष और राज्य-वार कितने संदिग्ध अवैध खनन मामलों का पता चला है;
(ख) अवैध खनन हॉटस्पॉट के रूप में पहचाने गए जिलों का ब्यौरा क्या है, ऐसी पहचान के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं और ऐसे प्रत्येक जिले में राज्य-वार और संघ राज्यक्षेत्र-वार एमएसएस अलर्ट की संख्या कितनी है;
(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान कितने एमएसएस अलर्ट सत्यापित मामलों में अवैध खनन सिद्ध किया गया था, शास्तियाँ लगाई गई और कितने मूल्य के खनिज बरामद किए गए या कितनी क्षतिपूर्ति प्राप्त की गई; और
(घ) क्या सरकार ने बार-बार होने वाले अवैध खनन हॉटस्पॉट अथवा कम सत्यापन दरों वाले राज्यों के प्रवर्तन निष्पादन की समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और निष्कर्ष क्या हैं तथा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

उत्तर

कोयला और खान राज्य मंत्री
(श्री सतीश चंद्र दुबे)

(क): पिछले पांच वर्षों (2021-22 से 2025-26) के दौरान, खनन निगरानी प्रणाली (एमएसएस) के माध्यम से कुल 679 ट्रिगर्स उत्पन्न किए गए हैं और 42 मामलों में अनधिकृत खनन की पुष्टि की गई है। पिछले पांच वर्षों के दौरान उत्पन्न ट्रिगर्स का राज्य-वार विवरण और उनका क्षेत्र सत्यापन अनुलग्नक-**I** में दिया गया है।

(ख): एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 23ग के अनुसार, राज्य सरकारों को खनिजों (प्रमुख खनिजों और गौण खनिजों दोनों) के अवैध खनन, ढुलाई और भंडारण निवारण और

उससे जुड़े प्रयोजनों के लिए नियम बनाने का अधिकार दिया गया है। तथापि, एमएसएस पोर्टल के अनुसार, राज्य-वार और ज़िला-वार उन ट्रिगर्स की संख्या, जहां राज्य सरकार द्वारा क्षेत्र सत्यापन के उपरांत अवैध खनन की पुष्टि की गई है, अनुलग्नक-**II** में दी गई है।

(ग) और (घ): खनन निगरानी प्रणाली (एमएसएस), अवैध खनन का पता लगाने के लिए राज्य सरकारों द्वारा पहले से स्थापित प्रणालियों के अलावा एक पूरक उपकरण के रूप में कार्य करती है। खनन निगरानी प्रणाली (एमएसएस) के तहत अनधिकृत खनन का संकेत देने के लिए उत्पन्न ट्रिगर्स को क्षेत्र सत्यापन के लिए संबंधित राज्य सरकारों को भेजा जाता है। ट्रिगर्स का सत्यापन संबंधित राज्य सरकारों के जिला-स्तर अधिकारियों द्वारा किया जाता है। इसके अलावा, अवैध खनन एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 23ग के अनुसार राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है, जिसके तहत राज्य सरकारों को खनिजों के अवैध खनन, ढुलाई और भंडारण निवारण और उससे जुड़े प्रयोजनों के लिए नियम बनाने का अधिकार है। परिणामस्वरूप, राज्य सरकारें ऐसे ट्रिगर्स के माध्यम से अवैध खनन का पता चलने पर कार्रवाई करती हैं, इसलिए एमएसएस ट्रिगर्स के आधार पर बने मामलों में लगाई गई और वसूल की गई शास्तियों या मुआवजे का विवरण संबंधित राज्य सरकारों के पास उपलब्ध होता है।

*****

<u>अनुलग्नक-I</u>

पिछले पांच वर्षों के दौरान उत्पन्न ट्रिगर्स और उनके क्षेत्र सत्यापन के राज्य-वार विवरण की स्थिति।

राज्य	2021-22		2022-23		2023-24		2024-25		2025-26		कुल	
	एमए सएस ट्रिगर्स की संख्या	पहचाने गए अनधिकृत खनन मामले	एमए सएस ट्रिगर्स की संख्या	पहचाने गए अनधिकृत खनन मामले	एमएस एस ट्रिगर्स की संख्या	पहचाने गए अनधिकृत खनन मामले	एमएस एस ट्रिगर्स की संख्या	पहचाने गए अनधिकृत खनन मामले	एमएस एस ट्रिगर्स की संख्या	पहचाने गए अनधिकृत खनन मामले	एमएस एस ट्रिगर्स की संख्या	पहचाने गए अनधिकृत खनन मामले
आंध्र प्रदेश	28	4	9	0	10	0	8	0	12	0	67	4
असम	-	-	-	-	2	0	-	-	-	-	2	0
बिहार	0	0	1	0	1	0	-	-	-	-	2	0
छत्तीसगढ़	23	0	8	0	29	0	10	0	6	0	76	0
गोवा	3	1	15	10	10	6	1	0	-	-	29	17
गुजरात	34	4	15	1	14	0	19	2	3	0	85	7
हिमाचल प्रदेश	-	-	-	-	3	0	5	0	1	0	9	0
जम्मू और कश्मीर (सं.रा.क्षे.)	4	0	-	-	7	0	13	1	-	-	24	1
झारखंड	5	0	17	0	7	0	6	0	1	0	36	0
कर्नाटक	4	0	13	0	5	1	6	1	3	0	31	2
केरल	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	1	0
मध्य	27	1	16	0	24	2	26	3	6	0	99	6

प्रदेश												
महाराष्ट्र	3	1	12	0	7	0	3	0	0	0	25	1
मेघालय	10	0	4	0	22	0	12	0	9	0	57	0
ओडिशा	7	0	4	0	2	0	7	0	7	0	27	0
राजस्थान	14	1	11	0	2	0	10	0	3	0	40	1
तमिलनाडु	13	0	13	2	7	0	8	1	17	0	58	3
तेलंगाना	1	0	-	-	3	0	1	0	-	-	5	0
उत्तर प्रदेश	1	0	-	-	2	0	3	0	-	-	6	0
										कुल योग	679	42

अनुलग्नक-II

ट्रिगर्स की राज्य-वार, जिला-वार संख्या, जहां राज्य सरकार द्वारा अनधिकृत खनन की पुष्टि की गई है

राज्य/जिला	ट्रिगर्स की संख्या, जहां राज्य सरकार द्वारा अनधिकृत खनन का पता किया गया
आंध्र प्रदेश	4
गुंटूर	1
कुरनूल	2
श्री पोटी श्रीरामुलु नेल्लोर	1
गोवा	17
उत्तर गोवा	6
दक्षिण गोवा	11
गुजरात	7
गिर सोमनाथ	1
जूनागढ़	1
खेड़ा	2
पोरबंदर	3
जम्मू और कश्मीर (सं.रा.क्षे.)	1
पुलवामा	1
कर्नाटक	2
मैसूर	1
तुमकुर	1
मध्य प्रदेश	6
जबलपुर	2
कटनी	1
सतना	3
महाराष्ट्र	1
चंद्रपुर	1
राजस्थान	1
सिरोही	1
तमिलनाडु	3
डिंडीगुल	1
करूर	2
कुल योग	42